

सम्पादकीय



गली छाप गुंडा

हर शहर में, हर गली में एक गुंडा होता है। जो कुछ लोगों को जमा कर गली के दुकानदारों और धनि लोगों से पैसे उगाही करता है। आम लोगों को डराना धमकाना उस का काम होता है। देखते, देखते वह गुंडा कुछ लोगों का ‘हीरो’ बन जाता है। उस का प्रभाव अपनी गली से दूसरी गलियों तक पहुँचता है। ख़ुब हय़ाम की कमाई इकट्ठ करता है। और इस हय़ाम की कमाई से कुछ पोलिटिकल पार्टियों को दान देता है। जो पार्टी पावर में हो उसे अधिक दान देता है। फिर किसी पार्टी का टिकट ख़रीद कर चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है! फिर एक दिन किसी विभाग का मिनस्टर भी बन जाता है। उस की पार्टी को पता है कि उस के पास धन शक्ति और मानव शक्ति है जो पार्टी के लिए वोट जुटा शक्ति है। मंत्री बनने के बाद वह गुंडा व्यापारियों और उद्योगपतियों से धन उगाही करता है। उगाहे हुए धन में से दस प्रतिशत दान कर बड़ा दानवीर बन जाता है। यह सारी बातें समाज का एक हिस्सा है। यह सब सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा।

लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति किसी देस का नेता बन जाता है तो क्या होता है? वह दुसरे देशों को धमकाने लगता है। और समझता है कि दुनिया में केवल वही अकलमन्द है। अगर उस के पास सत्ता है तो वह कुछ भी बोलता है। औरों को दबाता है। और दुसरे कमजोर देश के नेता उस के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं शेर का सामना करने कि हिम्मत रखते हैं।

ऊपर लिखी सारी बातें आज यदि सब से अधिक फिट बैठती हैं तो वह है अमरीका के प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्प। दूसरी बार जीतने के पश्चात् ट्रम्प ने अपने पड़ोसियों और दूर के देशों को धमकाना शुरू किया। भारत जैसे कुछ देश उस का सामना नहीं कर सके। उस ने जो चाहा करवाया। कुछ को कबाड़ जैसे युद्ध जहाज़ बेचने के लिए मजबूर किया। मैक्सिको, केनेडा जैसे पड़ोसियों पर टैरिफ़ लगा कर दौ। टैरिफ़ अर्थात आयातित शुल्क। केनेडा को अमरीका का 51 व राज्य बनने कि सलाह तक दे डाली। ट्रम्प भूल गए कि मैक्सिको, केनेडा अगर कुछ वस्तुएँ अमरीका से आयात करते हैं तो अमरीका भी उन देशों से कई वस्तुएँ आयात करते हैं। केनेडा और मैक्सिको ने जवाबी हमला करते हुए अमरीका से आयात होने वाली हर वास्तु और सेवा पर टैरिफ़ लगा कर ट्रम्प को जता दिया कि हम भी तुम से कम नहीं हैं। केनेडा, मैक्सिको ने अमरीका का मुकाबला करने की जो हिम्मत दिखाई वह हिम्मत भारत नहीं बता सका। भारत ने अमरीका से आयात होने वाली विद्युत कारों और शराब पर आयातित शुल्क बहुत कम कर दिए! इतना ही नहीं भारत के प्रधान मंत्री की उपस्थिति में ब्रिक्स संगठन को ‘मुदा’ घोषित कर दिया। याद रहे भारत इस संगठन के संस्थापकों में से एक है। भारत का इतना बड़ा अपमान इस से पहले कभी नहीं हुआ। ट्रम्प द्वारा किए गए इस अपमान के कारण विश्व में भारत की शाख पर आँच आई है।

न्यायालय का कड़ा कदम और विपक्ष का दबाव हो सकते हैं इस्तीफ़े का कारण

नित्य चक्रवर्ती

मौजूदा नियमों के अनुसार, वर्तमान सीईसी को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी काम के लिए क़ानून का संरक्षण प्राप्त है। सरकार उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकती। संसद द्वारा उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन भाजपा और उसके सहयोगियों के पास भारी बहुमत होने के कारण अभी यह व्यवहारिक नहीं है। विपक्ष शायद दूसरी बार महाभियोग की कोशिश न करे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर बड़ी उत्स़्खन में हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज़ानेश कुमार के इस्तीफ़े की विपक्ष की मांग से कैसे निपटा जाए। मौजूदा हालात अस्थिर हैं और मामला सीईसी को हटाने की मांग से आगे बढ़कर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफ़े तक भी जा सकता है, जो दिल्ली में अधोषि़त लोकडउन लगाए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को दबाने के फैसलों के पीछे मुख्य व्यक्ति रहे हैं।

आइए सबसे पहले चुनाव आयोग की बात करते हैं। सीईसी ज़ानेश कुमार 26 जनवरी, 2029 को रिटायर करने वाले हैं, जो अप्रैल/मई 2029 में होने वाले अगले लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक दो महीने पहले का समय है। मौजूदा दो चुनाव आयुक्तों में से सबसे वरिय डॉ. सुखबीर सिंह संघू 5 जुलाई, 2028 को रिटायर होंगे। दूसरे, डॉ. विवेक जोशी, 18 फ़रवरी, 2031 को रिटायर होंगे। इसलिए, अप्रैल/मई 2029 में अगले लोकसभा चुनावों के समय, मौजूदा तीन सदस्यीय ईसी में से केवल डॉ. विवेक जोशी ही बचे रहेंगे। सरकार को जुलाई 2028 के बाद एक नया चुनाव आयुक्त नियुक्त करना होगा।

मौजूदा नियमों के अनुसार, वर्तमान सीईसी को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी काम के लिए क़ानून का संरक्षण प्राप्त है। सरकार उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकती। संसद द्वारा उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन भाजपा और उसके सहयोगियों के पास भारी बहुमत होने के कारण अभी यह व्यावहारिक नहीं है। विपक्ष शायद दूसरी बार महाभियोग की कोशिश न करे। मोदी सरकार के पास उनके कार्यकाल के पूरा होने से पहले उनसे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका यही है कि उनसे खुद इस्तीफ़ा करने के लिए क़हा जाए। ज़ानेश कुमार को मोदी-भयत माना जाता है। केरल सरकार में सचिव रहते हुए उन्होंने मोदी और भाजपा के लिए काम किया है। अगर हालात की मांग हुई तो वह प्रधानमंत्री की बात मान सकते हैं। ज़ानेश कुमार, जिन्हें ‘टास्क मास्टर’ माना जाता है, भाजपा में शामिल हो सकते हैं और मंत्री भी बन सकते हैं।

लेकिन यह इस्तीफ़ा दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग और उसके तीनों सदस्यों को नोटिस भेजकर पूछा है कि क्या फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। अगर फैसले सर्वसम्मति से नहीं लिए गए थे, तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें रद्द कर सकता है। अब सवाल यह है कि ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की खबर की सच्चाई जानने के लिए सर्वोच्च न्यायालय दोनों चुनाव आयुक्तों से आमने-सामने बात करने में कितना आगे आएगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ़ चुनाव आयोग के आधिकारिक जवाब को मान लेता है, तो इसका कोई खास मतलब नहीं होगा, क्योंकि सीईसी बाकी दोनों पर दबाव डालकर संयुक्त बयान जारी करवा सकते हैं कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे।

ओपन माइंड होकर बात करना

व्यक्ति को ओपन माइंड होना जरूरी है, किसी भी शख्स से बात करने के लिए क्योंकि बात सुनना बात करना और फिर किसी के ऊपर राइट बनाना इसमें तभी हम अंतर ला सकते हैं , जब दो व्यक्ति आपस में ओपन माइंड होकर बात करें क्योंकि जब तक व्यक्ति खुले दिमाग से अपने विचारों को प्रकट नहीं करता है जब तक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मन की बातों को सामने वाले को समझाने में पीछे रह जाता है।



करिश्मा गुज्जर (खामी)

सचिन कुमार गौतम

लोकतंत्र में जनता की नाराजगी की अभिव्यक्ति के लिए दशकों से महत्वपूर्ण स्थल बन चुके जंतर-मंतर पर अब सरकार की नजर पड़ चुकी है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के 11 अक्टूबर 2026 के आदेश के बाद जंतर-मंतर रोड को तय प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि पिछले दो-ढाई दशकों से कई ऐतिहासिक आंदोलनों, जन-विरोधों और नागरिक संघर्षों का गवाह रहा जंतर-मंतर अब प्रदर्शन के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। सरकार का तर्क है कि इससे यातायात, कारोबार और मध्य दिल्ली की सामान्य गतिविधियों को राहत मिलेगी। लेकिन विपक्ष और नागरिक अधिकारों से जुड़े लोग इसे केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि विरोध की आवाज को हाशिए पर धकेलने की कोशिश मान रहे हैं।

जंतर-मंतर: विरोध की पहचान

दिल्ली में संसद भवन, सरकारी दफ्तरों और प्रशासनिक संस्थानों से कुछ ही दूरी पर स्थित जंतर-मंतर लंबे समय से राजनीतिक विरोध और जन आंदोलनों का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां केवल भाषण नहीं होते थे; यहां आम नागरिक, छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल अपनी मांगें सीधे सत्ता के सामने रखते थे। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह रही कि यह स्थान मीडिया के लिए भी सुलभ था और दिल्ली के केंद्र में होने के कारण वहां उठी आवाज राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचती थी।

पिछले 20-25 वर्षों में जंतर-मंतर पर कई बड़े आंदोलन हुए। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का आंदोलन, निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा की मांग, किसानों के अधिकारों को लेकर प्रदर्शन, छात्र संगठनों के विरोध, टेड यूनिवर्स को हड़तालें और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर नागरिकों की सभाएं—इन सबने जंतर-मंतर को लोकतंत्र का एक प्रतीक बना दिया। यहां खड़े लोगों ने कई बार सरकारों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए

मजबूर किया। इसलिए जंतर-मंतर केवल दिल्ली की एक सड़क या मैदान नहीं, बल्कि जनता और सत्ता के बीच संवाद का एक प्रतीकात्मक पुल रहा है।

नया आदेश और विकल्प

अब दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर की जगह रामलीला मैदान, पूर्वी दिल्ली के शाहदरा स्थित सीबीडी ग्राउंड और उत्तरी दिल्ली के



बुराड़ी ग्राउंड को प्रदर्शन स्थल के रूप में चिह्नित किया है। पुलिस का कहना है कि जंतर-मंतर पर बार-बार होने वाले प्रदर्शनों से मध्य दिल्ली में यातायात जाम, कारोबार में बाधा और आम जनजीवन प्रभावित होता है। साथ ही यह इलाका स्वेदनशील सरकारी इमारतों और दफ्तरों के निकट होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से भी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और अब भाजपा नेता किरण बेदी ने भी कहा है कि जंतर-मंतर

प्रदर्शन के लिए उपयुक्त जगह नहीं है, क्योंकि वहां के रास्ते संकरे हैं और आसपास कई महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थित हैं। लेकिन यह बहस केवल यातायात और सुरक्षा तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि क्या प्रदर्शन के अधिकार को ऐसी जगहों पर खिसकाना, जहां पहुंचना कठिन हो और मीडिया की पहुंच कम हो, लोकतंत्र के हित में है?

प्रदर्शन के लिए उपयुक्त जगह नहीं है, क्योंकि वहां के रास्ते संकरे हैं और आसपास कई महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थित हैं। लेकिन यह बहस केवल यातायात और सुरक्षा तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि क्या प्रदर्शन के अधिकार को ऐसी जगहों पर खिसकाना, जहां पहुंचना कठिन हो और मीडिया की पहुंच कम हो, लोकतंत्र के हित में है?

विपक्ष के सवाल

इस फैसले के समय दिल्ली में ज़ानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि

जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों से हटाने का फैसला संयोग नहीं है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार लोगों को उन जगहों से दूर रखना चाहती है, जहां से जनता का गुस्सा सत्ता तक सीधे पहुंच सकता है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नई पीढ़ी के विरोध



प्रदर्शनों से घबराए हुए हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इसे व्यंग्य के साथ ‘डेमोकुसी’ अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता। शाहदरा और बुराड़ी के मैदान दिल्ली के किनारों पर हैं, जहां पहुंचना, तमाम लोगों के लिए असुविधाजनक हो सकता है।

इस फैसले के समय दिल्ली में ज़ानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि

ज्ञान के समुद्र को सूखने मत दीजिए

भारतीय भाषाओं की पुस्तकें थीं। दिल्ली मेट्रो निर्माण के कारण 2011 में इसे अस्थायी रूप से बंद किया गया, लेकिन डेढ़ दशक बीतने को है और दो लाख से अधिक पुस्तकें अब भी डिब्बों में बंद हैं, पाठकों और शोधकर्ताओं की पहुंच से दूर। एक ओर केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालयों का महत्व इसलिए लोकतंत्र के बुनियादी चरित्र से जुड़ा है। वे पाठकों को विविध विचारों, इतिहास की अलग-अलग व्याख्याओं और परस्पर विरोधी मतों से परिचित करते हैं। 1911 में सम्राट जॉर्ज प्रथम द्वारा ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा के साथ 1891 में स्थापित इम्पीरियल सेक्रेटैरिएट लाइब्रेरी भी दिल्ली लाई गई। पहले इसे सिविल लाइंस स्थित ओल्ड सेक्रेटैरिएट भवन, फिर नॉर्थ ब्लॉक और अंततः 1969 में शास्त्री भवन में स्थान मिला। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय यानी सेंट्रल सेक्रेटैरिएट लाइब्रेरी के नाम से पहचानी जाने वाली लगभग 135 वर्ष पुरानी यह संस्था आज फिर विस्थापन के संकट में है। सवाल केवल 8.5 लाख से अधिक पुस्तकों को रखने की जगह का नहीं, बल्कि इस ज्ञान-संग्रह के संरक्षण और भावी पीढ़ियों तक इसकी पहुंच के प्रति हमारे संकोच का भी है।

इसी प्रश्न को तुलसी सदन पुस्तकालय की कहानी और व्यापक बनाती है। रामचरितमानस के 400 वर्ष पूरे होने पर 1972 में स्थापित इस पुस्तकालय में 14 भारतीय भाषाओं की पुस्तकें थीं। दिल्ली मेट्रो निर्माण के कारण 2011 में इसे अस्थायी रूप से बंद किया गया, लेकिन डेढ़ दशक बीतने को है और दो लाख से अधिक पुस्तकें अब भी डिब्बों में बंद हैं, पाठकों और शोधकर्ताओं की पहुंच से दूर। एक ओर केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालयों का महत्व इसलिए लोकतंत्र के बुनियादी चरित्र से जुड़ा है। वे पाठकों को विविध विचारों, इतिहास की अलग-अलग व्याख्याओं और परस्पर विरोधी मतों से परिचित करते हैं। 1911 में सम्राट जॉर्ज प्रथम द्वारा ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा के साथ 1891 में स्थापित इम्पीरियल सेक्रेटैरिएट लाइब्रेरी भी दिल्ली लाई गई। पहले इसे सिविल लाइंस स्थित ओल्ड सेक्रेटैरिएट भवन, फिर नॉर्थ ब्लॉक और अंततः 1969 में शास्त्री भवन में स्थान मिला। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय यानी सेंट्रल सेक्रेटैरिएट लाइब्रेरी के नाम से पहचानी जाने वाली लगभग 135 वर्ष पुरानी यह संस्था आज फिर विस्थापन के संकट में है। सवाल केवल 8.5 लाख से अधिक पुस्तकों को रखने की जगह का नहीं, बल्कि इस ज्ञान-संग्रह के संरक्षण और भावी पीढ़ियों तक इसकी पहुंच के प्रति हमारे संकोच का भी है।

नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के विनाश की ऐतिहासिक स्मृति हमें चेताती है कि ज्ञान की धरोहर का नष्ट होना केवल पुस्तकों का नष्ट होना नहीं, बल्कि सभ्यता की स्मृति को क्षति पहुंचाना भी है। इतिहास के ऐसे प्रसंगों से सबक लेते हुए हमें समझना होगा कि

पुस्तकालयों का संरक्षण केवल अतीत को संजचना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान और विचारों के रास्ते खुले रखना भी है। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थिति इसी कारण चिंताजनक है। शास्त्री भवन में लगभग 5,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में चार मंजिलों पर फैले इस पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकें, पुराने दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड और राजपत्र हैं। इसके दुर्लभ पुस्तक अनुभाग की सबसे पुरानी पुस्तक एक फ़ारसीय यंत्री के लेखों का संकलन है, जो 1702 का बताया जाता है। भारत सरकार के प्रकाशनों के महत्वपूर्ण भंडार के रूप में काम करने वाले इस पुस्तकालय का उपयोग अकादमियों में रखी पुस्तकों का समूह है? नहीं। वे किसी सभ्यता की स्मृति होते हैं। किसी समाज ने क्या सोचा, किन प्रश्नों से जुड़ा और विज्ञान, दर्शन, धर्म, साहित्य, किंवदंती तथा शासन के बारे में क्या समझ विकसित की—इन खबका प्रमाण पुस्तकों और अभिलेखों में मिलता है। इसलिए किसी पुस्तक का नष्ट होना केवल एक वस्तु का नष्ट होना नहीं है; उसके साथ अतीत को समझने का एक रास्ता भी बंद हो जाता है।

केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता केवल पुस्तकों को रखने के लिए नहीं है। संग्रह के संरक्षण, पाठकों और शोधकर्ताओं की सुविधा तथा पुस्तकालय की अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए भी उपयुक्त स्थान चाहिए। अब इस मामले ने सर्वोच्च न्यायालय का भी ध्यान खींचा है। न्यायालय ने 135 वर्ष पुराने पुस्तकालय के पुनर्वास का खर्च: संज्ञान लिया। कर्तव्य भवन-02 के भूतल पर दो कमरों का

प्रस्ताव संपद निदेशालय ने जनवरी में दिया था, जिसे संस्कृति मंत्रालय ने अर्पणित बताया था। अब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पुनर्विकास योजना में पुस्तकालय के लिए स्थान निर्धारित किए जाने और निर्माण प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी है। अंतिम कसौटी यही होगी कि यह स्थान पुस्तकालय के संग्रह, संरक्षण और पाठक सुविधा की जरूरतें पूरी करता है या नहीं।

पुस्तकालय का जीवन उसके पाठकों से है। दुर्लभ पुस्तकें यदि गोदामों में बंद रहें और शोधकर्ता उन तक न पहुंच सकें तो संरक्षण अधूरा है। केवल डिजिटलीकरण भी इसका विकल्प नहीं, क्योंकि मूल पुस्तक की भौतिक विशेषताएं और ऐतिहासिक संकेत डिजिटल प्रति में पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहते। इसलिए, डिजिटलीकरण और सबसे बढ़कर पाठकों-शोधकर्ताओं के लिए सहज पहुंच—इन सभी को समान महत्व देना होगा।

यहां प्रश्न केवल ‘विकास बनाम विरासत’ का नहीं है। असली प्रश्न यह है कि विकास की परिभाषा में ज्ञान और स्मृति के लिए कितनी जगह है। क्या आधुनिक भवनों के साथ हमारे पुराने ज्ञान-भंडार भी सुरक्षित रहेंगे, या पुस्तकालय विकास की दौड़ में पीछे छूट जाएंगे? और इससे भी बड़ा प्रश्न है—क्या हम उस ज्ञान-समुद्र को सूखने दे रहे हैं, जिससे समाज की ज्ञान-धारा निकलती है? किसी

पहला राउंड तो राहुल के नाम रहा

उसने इंडिया गठबंधन का प्रभावशाली रोड शो जरूर तैयार कर लिया और पहली बार ग्यारह दलों के नेता साथ दिखाई दिए। यह उनका साथ छोड़ने जा रही है। और इसके लिए उसने दिल्ली को छवनी में बदलने के लिए इटारसी तक से गिरफ्तारियां करने और ट्रेन, मेट्रो, बस बंद करने, दफ्तर दुकान बंद कराने तक से परहेज नहीं है।

जब एक बहुत ही ठेस तार्किक आधार पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस की तरफ से राहुल गांधी से मिलने से इंकार आ गया तो लागा कि मुख्य चुनाव आयुक्तज्ञानेश कु मार और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की गडबड़ियों के खिलाफ चलाने वाले आंदोलन को झटका लगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसी मामले में कई अर्जियों पर विचार कर रहे हैं इसलिए किसी एक पक्ष से मिलने का मतलब फैसले पर उसकी छवनी आने देना होगा। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप भी याचिका के माध्यम से आइए हम उस पर सुनवाई करेंगे। बाकी देश ने इस राय को सही माना लेकिन केरल कांग्रेस ने झट से मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ही पोस्ट किया पर उसे जल्दी हटाय़ा गया और कांग्रेस ने तुरंत नई याचिका बनाई जिसमें ज्ञानेश कुमार को हटाने की असेधव मांग भी है। सबको मात्तुम है कि यह काम सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन उसे दाखिल करने के बहाने

मुख्यमंत्रियों समेत सात हजार से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी और दिल्ली को छवनी में बदलने के बावजूद आंदोलनकारियों के हौसला ने सरकार को ही बैकफुट पर ला दिया था। लेकिन उसके नेताओं की सशर्त कोसिस के इस दांव से बना कि पहले दौर में उसकी बहुत हो गई। कांग्रेस ने आगे के लिए भी लंबा चौड़ा कार्यक्रम दिया है। भविष्यवाणी से बचना चाहिए लेकिन हमने देखा है कि ऐसा कार्यक्रम चलाना अब उसके संगठन के वश में नहीं रहता। राहुल कुछ कर जाते हैं और कांग्रेसी हम साथ लेते हैं। पर इसी के कारण कांग्रेस को छवनी में बदलने से दौरान कानूनी लड़ाई के नतीजे भी आएंगे। कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी नए राउंड दो की भी घोषणा कर रखी हैं। मौजूदा दौर में जिस तरह ज्ञानेश कुमार ने सैंकड़ों सांसदों के साथ जापन देने आए विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलने से इंकार किया उससे भी आंदोलन को बल मिला और आंदोलन पूरी श्रृंखला में आया। यह उम्मीद उस पर सुनवाई करेगे।

मामला सिर्फ कानूनी तरीकों से शांतिपूर्ण विरोध को रोकने का नहीं था। इस बार तो अदालती आदेश के बावजूद मेट्रो बंदी समेत अनेक काम हुए। दूसरी तरफ जुलाई वाली जंतर-मंतर की हिंसा के बाद भी अपराधियों और पुलिस की बर्दी में गुंटे उतारने का खेल बंद नहीं हुआ जिसको लेकर दुनिया भर में थू थू हुई। इस बार ऐसे गुंडे और पुलिस ने पत्रकारों, खासकर यूट्यूबयों को भी निशाना बनाया

और भाजपा के प्रवक्ता दिन भर कूर्ता बंडी चढ़ाए रेडी रहे और टीवी चैनलों पर उ नका प्रसारण जारी रहा। हां, जिम्मेदार बड़े नेता जरूर मीडिया में आने से बचते हैं। दिल्ली को छवनी में बदलने और शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों के खिलाफ गैर जरूरी सख्ती ने आम लोगों को भी भाजपा से नाराज किया।

अब इस आंदोलन के राजनैतिक रंग लेने और एक दौर में विपक्ष के बढ़त बढ़ाने के कई मतलब हैं। राहुल-प्रियंका फोकस में रहे और बहुत योजना से बनाए गए। लेकिन इन आंदोलन ने इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया। इसमें आईसा की आमद मजबूती वाला पक्ष बनी। इसमें ममता बनर्जी की सक्रियता एक नई चीज है। दूसरे यह भी हुआ कि बीजू जनता दल और द्रमुक कांग्रेस से नाराजगी के बावजूद एनडीए में जाने से बचे ही नहीं बीजद तो आंदोलन में शामिल भी हुआ। आंदोलन की एक स्वतंत्र धारा कॉकरोच जनता पार्टी की रही जिसने अपनी ताकत पहले दिखाई है और इस बार भी दस तारीख के उसके काल पर ही ज्यादा हंगामा हुआ। इसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया तब भी यह दमदार रहा और इसमें अरविन्द केजरीवाल के आप पार्टी सहित वाम दलों ने खुलकर भागीदारी की। कहना न होगा कि इस धारा के किए-धरे का राजनैतिक और चुनावी लाभ कांग्रेस को ही होगा और अगर भाजपा होशियारी से काम

विचार से है। ये टिप्पणियां तीखी जरूर हैं, लेकिन इनके पीछे की चिंता गंभीर है—कि क्या सत्ता विरोध को केवल व्यवधान समझकर उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है?

सरकार का तर्क और संदेह

सरकार का कहना है कि इस फैसले का ज्ञानेश कुमार विरोधी आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है। यह कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन को शहर के यातायात, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का ध्यान रखना होता है। बड़े प्रदर्शनों से आम नागरिकों को असुविधा भी होती है और कारोबार प्रभावित होता है। यह तर्क पूरी तरह बेतुका नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में प्रशासनिक सुविधा और नागरिक अधिकार के बीच संतुलन जरूरी है। यदि हर प्रदर्शन को यातायात या सुरक्षा की समस्या बताकर दूर के इलाकों में धकेल दिया जाए, तो विरोध की राजनीतिक और प्रतीकात्मक ताकत कमजोर होगी। जंतर-मंतर की अहमियत इसी बात में थी कि वह सत्ता के केंद्र के पास था। वहां खड़े प्रदर्शनकारी सरकार को यह याद दिलाते थे कि जनता दूर नहीं है। अब जब प्रदर्शनकारी शहर के किनारों पर जाएंगे, तो सत्ता और जनता के बीच की दूरी केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी बढ़ेगी।

जुलाई का जेन जेड आंदोलन

विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस साल जुलाई में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उठे जेन जेड आंदोलन ने जंतर-मंतर पर ही अपनी ताकत दिखाई थी। युवाओं का वह आंदोलन सरकार के लिए चेतावनी बन गया था। अब ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शनों के दौरान भी आंदोलनकारियों को जंतर-मंतर पहुंचने से रोकने की कोशिशें होती रही हैं। ऐसे में यह मानना स्वाभाविक है कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों से हटाने का निर्णय केवल प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। मोदी मोदी लोकतंत्र को भी प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि असली समस्या जगह नहीं, बल्कि लोगों के विरोध करने के

समाज की शक्ति उसके आधुनिक भवनों और डिजिटल साधनों के साथ-साथ इस बात से भी तय होती है कि वह अपने ज्ञान-संग्रह को कितना सुरक्षित रखता है। पुस्तकालयों का महत्व इसलिए लोकतंत्र के बुनियादी चरित्र से जुड़ा है। वे पाठकों को विविध विचारों, इतिहास की अलग-अलग व्याख्याओं और परस्पर विरोधी मतों से परिचित कराते हैं। इससे समाज किसी एक आख्यान या सत्ता-केंद्रित दृष्टि पर निर्भर रहने के बजाय प्रश्न करने, विचारों की तुलना करने और अपने निकर्ष स्वीय बनाने की क्षमता विकसित करता है। भारत के सामने आज अवसर है कि वह अपनी पुस्तकालय नीति को केवल भवन, बजट और पुस्तकों की संख्या तक सीमित न रखे। लखनऊ का मुंशी नवल किशोर प्रेस, रामपुर रज़ा पुस्तकालय, तुलसी सदन, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय और नार नाराय स्तर के पुस्तकालय हमारी ज्ञान-धरोहर की विविध परतों को सुरक्षित रखते हैं। इन्हें भी उतनी ही गंभीरता से संरक्षित किया जाना चाहिए, जितनी गंभीरता से हम अपने स्थापत्य स्मारकों की रक्षा करते हैं। आवश्यकता केवल केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय को पर्याप्त जगह देने या तुलसी सदन की पेटियां खोलने के नहीं, बल्कि ऐसी संस्कृति विकसित करने की है जिसमें पुस्तकालय खर्च नहीं, ज्ञान में निवेश है; दुर्लभ पुस्तकें पुराना कागज नहीं, सामूहिक स्मृति हैं; और पाठक ज्ञान-संपद का स्वाभाविक अधिकारी हैं।

लेती तो चुनाव आयोग की गलतियों से निपटने के साथ इस तरह के राजनैतिक विभाजन का लाभ लेने की कोशिश करती। हुआ यह कि चिराग पासवान सहित एनडीए के कई साथी शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थन में दिखे तो बाकी साथी भी उस तरह ज्ञानेश कुमार के फैसलों के पक्ष में न लगे। ज्ञानेश कुमार रहें या जाएं, यह विशेष पुनरीक्षण अभियान आगे जो रूप ले, राहुल गांधी और विपक्ष की राजनीति जहां तक जाए, इस आंदोलन की सफलता न सिर्फ जरूरी है बल्कि इस मुकल के लोकलरों के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रही है। भारतीयों, खासकर इस मुकल के गरीब गुरुबा और कमजोर जमातों को उनके हकों के प्रति जागरूक करने का काम सौ -डेड सौ साल से चल रहा है और अब जाकर समाज का कमजोर वर्ग उभरकर सामने आया है।

चुनाव और मतदान यह बताते हैं कि आजादी के बाद से ही पूरा परिदृश्य कैसे बदला है-मण्डल के बाद तो यह हर किसी को दिख रहा है। दूसरी ओर इस कमजोर जमात को भी यह लग गया है कि वैश्विक पूंजीवाद के आगे नाच के समय सचिवाय और मतदान का अधिकार न हो तो उनके लिए सांस लेना भी अब मुश्किल होगा। ऐसे में मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर तैर करेडो से ज्यादा नाम काटना सचमुच जीवन-मरण का सवाल है और अगर हमें खिलाफ आंदोलन की चेतना बनती और आगे बढ़ती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। इसी लिहाज से आंदोलन के पहले चरण की बहुत महत्वपूर्ण है।

फिल्म ‘नई नवेली’ से पहले राम दरबार पहुंचीं यामी गौतम, अयोध्या में टेका माथा



अभिनेत्री यामी गौतम अपनी आगामी फिल्म ‘नई नवेली’ की सफलता के लिए राम दरबार पहुंचीं। अभिनेत्री ने मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि वे पहली बार अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमान गढ़ी के दर्शन करने आई हैं। अभिनेत्री का कहना है कि वे अयोध्या की अध्यात्मिकता को करीब से देखना चाहती थीं। उन्होंने कहा, अभी मैं राम जन्मभूमि दर्शन करके हनुमान गढ़ी आई हूं। पहली बार मेरा अयोध्या नगरी में बहुत भावुकता और मन में श्रद्धा के साथ आना हुआ है। प्रभु श्री राम, हनुमान भगवान और माता रानी की कृपा से मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा रहा है और मैं कामना करती हूं कि जिसके लिए मैं यहां आई हूं, वो काम अच्छे से पूरा हो। यामी ने भगवान राम से जुड़े इस पवित्र भूमि पर आने का मौका मिलने पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, मैं यहां पर भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए आई हूं और इस पवित्र भूमि को करीब से देखना चाहती थी। मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे इस पवित्र भूमि के दर्शन करने का मौका मिला, जहां श्रीराम 14 साल तक रहे थे। अभिनेत्री यामी गौतम ने इंस्टाग्राम पर भी इस अध्यात्मिक यात्रा की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह सरयू घाट पर आरती में शामिल नजर आ रही हैं। मंदिर में दर्शन के लिए एक्ट्रेस ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी, जिसके साथ उन्होंने लंबे झुमके पहने थे। हल्के मेकअप के साथ उन्होंने अपने लुक को सिंपल और एलिगेंट रखा था। अभिनेत्री ने लिखा, अयोध्या में मां सरयू घाट पर आरती और मन में शांति। नवरात्रि के दिनों में इस पावन नगरी से आशीर्वाद मिला और मन भावुक हो गया। अब जो कल हो, सो ‘श्री राम की कृपा’। सभी सकारात्मकता और शुभकामनाओं के साथ, कल रिलीज होने वाली सभी फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नई नवेली शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। बालाजी मोहन द्वारा निर्देशित फिल्म नई नवेली में अभिनेत्री यामी गौतम मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं। यह फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। (एजेंसी)

जयन्मा के किरदार से प्रेरित हुईं रश्मिका मंदाना, अब 400 परिवारों के लिए उठाय़ा बड़ा कदम

रश्मिका मंदाना अपनी आने वाली फिल्म ‘रणबाली’ की रिलीज का इंतजार कर रही हैं। शादी के बाद यह उनकी पति विजय देवरकोंड के साथ पहली फिल्म है। फिल्म में रश्मिका ने जयम्मा का किरदार निभाया है। भारत के इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में से एक 1876-78 के भयंकर अकाल से प्रेरित इस फिल्म के किरदार ने रश्मिका को 400 परिवारों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। **400 परिवारों को तीन महीने तक देगी राशन** रश्मिका ने हाल ही में बताया कि उन्होंने 400 परिवारों को गोद लिया है और तीन महीने तक उनके लिए राशन का इंतजाम करेंगी। उनका मकसद है कि इन परिवारों के राशन का खर्च बचे और वे उस पैसे का इस्तेमाल अपने भविष्य की बेहतर योजना बनाने में कर सकें। रश्मिका ने इंस्टाग्राम पर अपनी टीम का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें परिवारों को राशन के पैकेट बांटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह पहले इस तरह के काम को सार्वजनिक नहीं करती थीं, लेकिन अब उन्होंने इसके बारे में बताने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इससे दूसरे लोग भी जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने लिखा, ‘आप जो किरदार निभाते हैं, उनमें कुछ ऐसा होता है जो आपको प्रभावित करता है।’ रश्मिका ने आगे बताया



कि कई लोग उनसे पूछते हैं कि क्या जयम्मा और उनमें कोई समानता है। उनका जवाब हां है और लोगों की मदद करना उनमें से एक है। **अगर इससे कोई और प्रेरित हो सके तो मुझे खुशी होगी** रश्मिका ने कहा कि वह हमेशा से इस तरह की मदद करती रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने इस बारे में इसलिए नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वह, उनकी टीम और कुछ करीबी लोग इसके बारे में जानते हैं तो इतना काफी है। अब उन्होंने इसके बारे में बताते हुए कहा, ‘अगर इससे आप लोगों को भी ऐसा कुछ करने की प्रेरणा मिल सके, तो मुझे खुशी होगी।’ उन्होंने कहा कि इसी वजह से उन्होंने अब इसकी शुरुआत सार्वजनिक रूप से करने का फैसला किया है। रश्मिका ने बताया कि उन्होंने आज 400 परिवारों को गोद लिया है और वह हर बार 400 परिवारों की तीन महीने तक मदद करना चाहती हैं। वह आगे एक साल तक इस काम को जारी रखने की उम्मीद कर रही हैं। उन्होंने कहा, छोटी सी भी दयालुता किसी की जिंदगी बदल सकती है और इसके लिए कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आइए, हम सभी किसी छोटी चीज से शुरूआत करें। रश्मिका ने अपनी टीम द्वारा परिवारों को राशन बांटने का वीडियो भी साझा किया। (एजेंसी)



जिस हेमा मालिनी पर फिदा है पूरा बॉलीवुड, कभी उन्हें निर्देशक ने फिल्म से कर दिया था बाहर

हेमा मालिनी उन चुनिंदा अदाकाराओं में शामिल हैं, जिनकी खूबसूरती, शानदार डांस और दिलकश अदाओं ने दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। 70 और 80 के दशक में हेमा मालिनी का जादू ऐसा था कि हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। उनकी मुस्कान और चुलबुला अंदाज लोगों को दीवाना बना देता था। क्या आप जानते हैं कि जिस हेमा मालिनी पर बाद में पूरा बॉलीवुड फिदा हो गया, उन्हें करियर की शुरुआत में एक निर्देशक ने फिल्म से बाहर कर दिया था? इतना ही नहीं, उनसे यह तक कह दिया गया था कि वह कभी अभिनेत्री नहीं बन सकतीं।

हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मां जया चक्रवर्ती फिल्म निर्माण से जुड़ी थीं। घर में फिल्मी माहौल होने के कारण हेमा का रुझान भी फिल्मों और कला की ओर था। हालांकि, उनकी मां चाहती थीं कि वह एक बेहतरीन डांसर बनें। हेमा ने कम उम्र में ही नृत्य सीखना शुरू कर दिया था और धीरे-धीरे अपनी करीब से पहचान बनाने लगीं। फिल्मों में जगह बनाना उनके लिए आसान नहीं रहा। हालांकि 13-14 साल की उम्र में उन्हें तमिल फिल्म ‘वेन्निरा अर्दाई’ में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का निर्देशन सीवी श्रीधर कर रहे थे। शुरुआत

में हेमा को फिल्म के लिए चुन लिया गया और उनके कुछ शॉट्स भी शूट किए गए। उन्हें लगा कि अब उनके अभिनय करियर की शुरुआत हो जाएगी लेकिन कहानी ने अचानक दूसरा मोड़ ले लिया। कुछ दिनों की शूटिंग के बाद निर्देशक ने उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया। हेमा मालिनी ने बाद में अपनी किताब ‘बिगॉन्ड द ड्रीमगल्ट’ के विमोचन के दौरान इस घटना का जिक्र किया था। उनके मुताबिक, निर्देशक ने उन्हें यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि वह बहुत दुबली-पतली हैं और अभिनेत्री बनने के लिए लायक नहीं हैं। यह बात इतनी कम उम्र में सुनना हेमा को लिए किसी बड़े

झटके से कम नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ दिन शूटिंग करने के बाद उन्हें अचानक क्यों हटा दिया गया। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि वह मानसिक रूप से कितनी परेशान हो गई थीं। फिल्म से निकाले जाने के बाद वह काफी असहज महसूस करने लगी थीं। उन्हें डर था कि कहीं लोग उनका मजाक न उड़ाने लें और उनके डांस कार्यक्रमों में आना बंद न कर दें। एक तरफ वह अपने डांस के जरिए पहचान बना रही थीं, तो दूसरी तरफ फिल्मों में मिली इस नाकामी ने उनके आत्मविश्वास को झटका दिया था। (एजेंसी)



करिश्मा कपूर की छोटी ड्रेस देख मड़क गए थे सलमान? कॉफी विद करण 9 में एक्ट्रेस ने सुनाया पुराना किस्सा

बॉलीवुड डायरेक्टर करण जोहर अपने चैट शो कॉफी विद करण सीजन 9 के साथ लौट आए हैं। शो का पहला एपिसोड 14 अक्टूबर को रिलीज हुआ, जिसमें सलमान खान कई सीजन बाद नजर आए। इसी एपिसोड के बीच में करिश्मा कपूर भी शो का हिस्सा बनीं। बातचीत के दौरान करिश्मा ने सलमान से जुड़ा एक पुराना किस्सा बताया, जब एक गाने की शूटिंग के दौरान सलमान ने उनके कपड़ों को लेकर आपत्ति जताई थी। **करिश्मा की ड्रेस देखकर सलमान ने रोक दी थी शूटिंग?** कॉफी विद करण 9 में करिश्मा कपूर ने फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे के गाने प्यार दिलों का मेला है की शूटिंग से जुड़ा किस्सा सुनाया। करिश्मा ने बताया कि गाने की शूटिंग के लिए उन्होंने छोटी स्कर्ट और टॉप पहना था। सलमान खान को उनका ड्रेस देखने के बाद परेशानी हुई और उन्होंने गाने की शूटिंग करने से मना कर दिया। मामला बढ़ने पर करिश्मा को डायरेक्टर डेविड धवन के पास जाकर सलमान की शिकायत करनी पड़ी। इसके बाद डेविड धवन ने सलमान से बात की और उन्हें समझाया। इसके बाद सलमान शूटिंग करने के लिए तैयार हुए। सलमान खान ने शो में इस पुराने किस्से पर अपनी सफाई भी दी। उन्होंने बताया कि उन्हें करिश्मा की ड्रेस के छोटी या ज्यादा खुली होने से कोई परेशानी नहीं थी। उनकी आपत्ति की वजह कुछ और थी। सलमान ने कहा, ‘डांस के समय करिश्मा की स्कर्ट ऊपर खिसक जाती थी और हर टेक के बाद उसे सही करना पड़ता था। इसलिए मैंने आपत्ति जताई थी।’ यानी सलमान की परेशानी करिश्मा के कपड़ों से ज्यादा इस बात को लेकर थी कि डांस करते समय स्कर्ट बार-बार ऊपर खिसक रही थी और हर बार उसे ठीक करना पड़ रहा था। सलमान खान और करिश्मा कपूर ने 90 के दशक में कई फिल्मों में साथ काम किया है। (एजेंसी)

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में, मार्को रुबियो की भारत यात्रा से पहले हो सकता है ऐलान : सर्जियो गोर

नई दिल्ली (एजेंसी)

भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। अधिकांश प्रमुख मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और अब केवल कुछ शेष बिंदुओं पर बातचीत जारी है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने गुरुवार को यह जानकारी दी। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम में बोलते हुए गोर ने कहा कि प्रस्तावित समझौते का व्यापक ढांचा लगभग तैयार हो चुका है और उन्हें भरपूर है कि दोनों देश जल्द ही इसे अंतिम रूप दे देंगे। उन्होंने कहा, बड़ी तस्वीर, व्यापक ढांचा और प्रमुख मुद्दों पर काम पूरा हो चुका है। इस बीच, उन्होंने इन बातों को दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच होने वाली सबसे तेजी से आगे बढ़ रही व्यापार चर्चाओं में से एक बताया। गोर ने कहा कि बातचीत



अब उत्पाद-विशेष और शुल्क स्तर से जुड़े मुद्दों तक पहुंच चुकी है, जिसमें अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने माना कि दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत स्वाभाविक रूप से जटिल होती है, लेकिन दोनों देश समझौते को अंतिम रूप देने के बहुत करीब हैं। द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर प्रकाश डालते

हुए अमेरिकी राजदूत ने भारत को अमेरिका का एक भरपूरसमर्थन रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की सराहना की और कहा कि भारत है, जिन्हें महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी साझेदारियों में आमंत्रित किया गया। गोर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), प्रौद्योगिकी विकास, स्वच्छ ऊर्जा और

असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग दोनों देशों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडेबी और माइक्रोन जैसी प्रमुख अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ाए जा रहे निवेश का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी दोनों देशों के लिए लायकारी है और रोजगार सृजन में मदद करती है। रक्षा संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका के साथ अधिक संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है। हाल के संयुक्त अभ्यासों और भारत में एफ-35 लड़ाकू विमानों की भागीदारी को उन्होंने बढ़ते रणनीतिक विश्वास का प्रमाण बताया। गोर ने यह भी घोषणा की कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो जल्द ही भारत की यात्रा करेंगे। उनकी मुंबई और जामना में कई बैठकों और कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

भारत अगले 20-25 वर्षों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा : पीयूष गोयल

नई दिल्ली (एजेंसी)

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत अगले 20-25 वर्षों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दशकों में वैश्विक विकास और प्रौद्योगिकी उन्नति को गति देने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में है। गण्टीय राजधानी में आयोजित एसआरसीसी शताब्दी सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया के देश आज भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वे



इसकी युवा और महत्वाकांक्षी आबादी की क्षमता को पहचानते हैं। उन्होंने कहा, आज दुनिया भारत के साथ जुड़ना चाहती है, क्योंकि वह समझती है कि आकांक्षाओं से भरा युवा भारत वैश्विक विकास का नेतृत्व करने जा रहा है। भारत प्रौद्योगिकी और वैश्विक व्यापार में प्रगति का प्रमुख

इंजन बनने वाला है। भारत की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि देश को अपनी जनसांख्यिकीय बढत, विशाल उपभोक्ता बाजार और उद्यमशील ऊर्जा का लाभ मिलेगा, जिससे आने वाले दशकों तक विकास की गति बनी रहेगी। उन्होंने कहा, हम अगले 20-25 वर्षों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहेंगे। हमारी जनसांख्यिकीय क्षमता, युवा आबादी और बड़े बाजार को देखते हुए हम यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि भविष्य की दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 14 अक्टूबर तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन) 13.21 प्रतिशत बढ़कर 13.38 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। आयकर विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, कॉर्पोरेट टैक्स, गैर-कॉर्पोरेट टैक्स और सिविलीटीज ट्रांज़ैक्शन टैक्स (एसटीटी) से प्राप्त राजस्व में वृद्धि के चलते यह बढ़ोतरी की गई। रिफंड को समायोजित करने से पहले सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह (ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन) 14.89 प्रतिशत बढ़कर 16.03 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की



समान अवधि में यह 13.95 लाख करोड़ रुपए था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए रिफंड में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। रिफंड का आंकड़ा एक साल पहले के 2.13 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 24.22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान शुद्ध

कॉर्पोरेट कर संग्रह बढ़कर 5.99 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 4.97 लाख करोड़ रुपए था। वहीं, गैर-कॉर्पोरेट करों से शुद्ध संग्रह, जिसमें व्यक्तिगत और अन्य गैर-कॉर्पोरेट इकाइयों द्वारा चुकाए गए कर शामिल हैं, 6.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 6.92 लाख करोड़

रुपए हो गया। वहीं, सिविलीटीज ट्रांज़ैक्शन टैक्स (एसटीटी) से प्राप्तियों में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। शुद्ध एसटीटी संग्रह बढ़कर 46,840.43 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो एक वर्ष पहले 30,901.81 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि, अन्य करों की श्रेणी में शुद्ध संग्रह नकारात्मक रहा और यह घटकर माइनस 1.64 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि में 282.39 करोड़ रुपए था। वहीं, सकल आधार पर कॉर्पोरेट कर संग्रह बढ़कर 7.53 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 6.44 लाख करोड़ रुपए था। इसी प्रकार, सकल गैर-कॉर्पोरेट कर संग्रह 7.20 लाख

करोड़ रुपए से बढ़कर 8.03 लाख करोड़ रुपए हो गया। बयान के मुताबिक, सकल एसटीटी संग्रह भी बढ़कर 46,840.43 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो एक वर्ष पहले 30,901.81 करोड़ रुपए था। वहीं, अन्य करों के तहत सकल संग्रह 18.87 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष दर्ज 301.22 करोड़ रुपए से कम है। सरकार ने कहा है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़ों में कंपनियों के साथ-साथ व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ), फर्मों, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (एओपी), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (बीओआई), स्थानीय निकायों और कुत्रिम न्यायिक निकायों द्वारा चुकाए गए कर शामिल हैं।